*भारतीय भुगतान प्रणाली बहुरूपी**

एस. एस. मूंदड़ा

श्री एम. बालचन्द्रन, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय नैशनल भुगतान निगम (एनपीसीआई); श्री ए.पी. होता, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एनपीसीआई; एनपीसीआई बोर्ड के सदस्यों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण, सम्मेलन में भारत तथा विदेश से उपस्थित प्रतिनिधिगण; देवियो और सज्जनो ! यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रतिष्ठित समारोह के बीच ''राष्ट्रीय भुगतान योजनाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन'' की पूर्व संध्या पर विदाई भाषण देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित ही यह एनपीसीआई द्वारा अपनी ओर से एक अनोखी पहल है जो कि पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रों के बाजार सहभागियों तथा संस्थानों के बीच पारस्परिक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है।

2. सम्मेलन के पिछले डेढ़ दिन में मैंने यह देखा है कि विभिन्न देशों-दोनों विकसित और विकासशील से प्रतिनिधियों ने नवीन उपायों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं जिससे वे अनेक उत्पादों और सेवा प्रस्तावों के माध्यम से अपने-अपने देशों में भुगतान प्रणालियों में परिवर्तन ला रहे हैं। मैं यह समझता हूँ कि कार्ड भुगतान तंत्र और मोबाईल भुगतानों के साथ साइबर सुरक्षा,भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष, वैश्विक भुगतान प्रणालियों द्वारा चुनौतियों/अवसरों का सामना आदि पर विचार-विमर्श किया गया। मुझे यकीन है कि यहां उपस्थित आप सभी इस अनुभव बांटने वाली प्रक्रिया से बेहद लाभान्वित हुए होंगे और मेरा यह विश्वास है कि आपका विश्वभर में भिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्थाओं में परिचालित राष्ट्रीय भुगतान योजनाओं का बेहतर ज्ञान वर्धन हुआ होगा। मैं अपने भाषण में चाहता हूँ कि भारत में भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में हाल की गतिविधियों को संक्षेप में पता लगाया जाए, कतिपय मामलों और चुनौतियों, जिनकी निकट भविष्य में महत्वपूर्ण बनने की संभावना प्रतीत होती हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने में किए जानेवाले उपायों पर प्रकाश डाला जाए। हालांकि, मैं अर्थव्यवस्था के लिए भुगतान प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए शुरूआत करना चाहूँगा।

भुगतान प्रणाली का महत्व

3. हम सभी को ज्ञात है कि सुरक्षित, कुशल और प्रभावशाली भुगतान प्रणाली वित्तीय बाज़ारों के संचालन तथा आम तौर पर स्वयं अर्थव्यवस्था के लिए और भी महत्वपूर्ण होती है। भुगतान प्रणाली में किसी प्रकार की बाधा, वित्तीय बाज़ारों के कामकाज को बाधित करने की क्षमता रखता है और इससे प्रणालीगत अस्थिरता उत्पन्न होती है। जब हम ऐसी बड़ी बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो संभवतः हमारे ज़हन में और बड़ी तथा प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान मूलभूत सुविधा तथा ज्यादा भुगतान प्रणाली सदस्यों की अधिकतम संख्या अर्थात् वित्तीय संस्थानों, विनिमय निपटान प्रणाली, केंन्द्रीय काउंटर पार्टियां आदि का ध्यान आता है। इस वर्णक्रम की दूसरी ओर भुगतान प्रणाली को खुदरा ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती है। इन अर्थों में भुगतान प्रणाली में एक समावेशन अधिदेश भी होता है ताकि निधियों का विप्रेषण तथा छोटे मूल्य के भुगतान जैसे जनता की दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यहां इस बात पर ज़ोर देना जरूरी है कि केन्द्रीय बैंक और सरकार भी लोगों को नकद से दूर रखने और उन्हें कार्ड, मोबाइल,सीधे डेबिट आदि जैसे नकदीरहित साधनों की ओर प्रेरित करने के इच्छुक हैं।

वित्तीय समावेशन के प्रचार में भुगतान प्रणाली की भूमिका

4. मैं संक्षेप में वित्तीय समावेशन के प्रचार में भुगतान प्रणाली की भूमिका पर कहना चाहूँगा। वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों के बीच एक मज़बूत सहलग्नता होती है। वित्तीय समावेशन अपने सरलतम रूप में बैंकिंग समावेशन दर्शाता है जहाँ बैंक रहित जनसंख्या को उनके बैंक खाते खुलवाकर औपचारिक

* एनपीसीआई द्वारा 22 मई 2015 को राष्ट्रीय भुगतान योजनाओं पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर,भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदाई भाषण

बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लोगों के बीच बैंकिंग और बचत की आदत डालने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता हो जहां निधि को रखा जा सकता है - जो शुरुआत में केन्द्र/राज्य सरकार योजनाओं के अतंर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरणों के रूप में हो सकता है।

5. भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पीएमजेडीवाई योजना ने बैंक रहितों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने में आश्चर्यजनक सफलता हासिल की है। भारत में लगभग 99.99 प्रतिशत परिवारों के लिए बैंक खाते खोले गए जिससे बैंकिंग प्रणाली दायरे में 150मिल्यन नए ग्राहक जुड़ गए तथा लगभग 135 मिल्यन रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किए गए। ये बहुत बड़ी संख्या है जो एकल आधार पर है और लेन-देन मात्रा में इस बहुसंख्यक वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाना पड़ेगा। भुगतान प्रणाली को इतना मजबूत रखना होगा कि वह प्रतिदिन के नित नए लाखों लेन-देनों को संसाधित कर सके, उसका निपटान तथा मिलान कर सके। मुझे यकीन है कि यहां उपस्थित भारतीय प्रतिभागी सम्मेलन के दौरान सीखी अनेक प्रकार की भुगतान प्रणाली की मूलभूत सुविधाओं की जटिलताओं का लाभ उठायेंगे और इसे देश में भुगतान प्रणाली की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने में इस्तेमाल करेंगे ताकि बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत में भुगतान प्रणाली का उद्भव

6. अब मैं उन कतिपय महत्वपूर्ण गतिविधियों की ओर आता हूँ जो भारत की भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन और निगरानी में घटित हुई है।

- 1980 के आरंभ में चेक समाशोधन प्रणाली को यंत्रचालित करने हेतु एमआइसीआर समाशोधन की शुरूआत ।
- वर्ष 1996 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीबीआरटी) की स्थापना जिसका उद्देश्य विश्वसनीय संप्रेषण नेटवर्क का तकनीकी उन्नयन और विकास था।
- वर्ष 1990 में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का प्रारंभ।
- वर्ष 1990 में बैंकों द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति देना।
- वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच प्रारंभ करने से देश भर में एटीएम की इंटरकनेक्टिविटी।
- बैंकों द्वारा सीबीएस का प्रारंभ करना तथा सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2004 में आरटीजीएस और एनईएफटी प्रारंभ करना।
- चेक ट्रंकेशन प्रणाली (फरवरी 2008) तथा वर्धित विशेषताओं के साथ नया आरटीजीएस (अक्तूबर 2013) प्रारंभ करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (फरवरी 2009 में) विश्व में अपनी तरह का 'कार्ड मौजूद नहीं' लेन-देन के लिए दूसरा कारक प्रमाणीकरण प्रारंभ करना।
- रुपए-एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क (मार्च 2012) लांच करना।

7. मैं आपको हाल के वर्षों में भुगतान प्रणाली लेन-देनों में मात्रा और मूल्य में किस प्रकार से वृद्धि हुई वह बताना चाहूँगा। मात्रा के संदर्भ में आरटीजीएस में किए गए लेन-देनों की संख्या मार्च 2013 में अंत तक 68.51 मिल्यन थी जो बढ़कर मार्च 2015 के अंत तक 92.77 मिल्यन हो गई। इसी अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में ये लेन-देन रु.677 ट्रिल्यन से बढ़कर रु.754 ट्रिल्यन हो गए। खुदरा भुगतानों (पेपर समाशोधन और खुदरा इलेक्ट्रानिक समाशोधन सहित) के अंतर्गत मार्च 2013 के अंत में संभाली गई मात्रा 694 मिल्यन थी जो मार्च 2015 के अंत तक 1687 मिल्यन हो गई जोकि दो गुना से भी ज्यादा थी। उसी प्रकार, मूल्य के संदर्भ

में भी यह रु.32 ट्रिल्यन से दुगुना से ज्यादा रु.65 ट्रिल्यन हो गया। साथही, कार्ड भुगतानों की मात्रा और मूल्य में भी इस अवधि के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में दुगुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। मार्च 2015 की समाप्ति पर लेन-देनों की मात्रा 1,737 मिल्यन थी जिसका मूल्य रु.3.3 ट्रिल्यन था। देश में आर्थिक विकास के स्तर को देखते हुए ये संख्या बहुत प्रभावशाली है लेकिन जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया था आगे बढ़ते हुए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। यदि नकदी से उपभोक्ताओं को छुड़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना हो तो हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है ताकि हम अधिकाधिक संख्या में लेनदेनों को सुरक्षित, सकुशल और सक्षम तरीके से संभाल सकें।

8. मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के लिए फिलहाल विभिन्न उपक्रम किए जा रहे हैं जिसमें कारोबारी प्राप्त राशियां तथा डिस्काउंट प्रणाली और भारत बिल भुगतान प्रणाली शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक पहले 2012-15 के लिए एक विज़न डाक्युमेंट लेकर आया था और उसमें निहित अधिकांश उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं। रिज़र्व बैंक का विज़न यह सुनिश्चित करना है कि ''देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां सुरक्षित, सक्षम, अंतः प्रचालनीय, प्राधिकृत, सुलभ, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अनुपालन योग्य हैं"। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया था कि एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के लिए एक मजबूत और सक्षम भुगतान प्रणाली प्रथम आवश्यकता है। लेन-देनों की बढ़ती मात्रा और मूल्य के चलते केन्द्रीय बैंक भुगतान प्रणालियों को नज़रअंदाज करने का जोखिम नहीं ले सकते। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है।

एनपीसीआई की भूमिका

9. इस सम्मेलन के सत्रों के दौरान आपको एनपीसीआई की भूमिका की विस्तृत जानकारी मिल ही गई होगी। चूंकि मुझे कुछ समय के लिए एनपीसीआई के बोर्ड में सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था इसलिए मैं एनपीसीआई की भूमिका और उपलब्धियों पर कुछ शब्द बोलना चाहुँगा। इसकी स्थापना समान कारोबार प्रक्रियाओं के साथ पैन-इंडिया भुगतान प्रणालियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी और इसने इस बड़े काम से निपटने के लिए पहले ही एक सक्षम ईको प्रणाली तैयार कर दी है। एनपीसीआई की कतिपय उपलब्धियां जिसने उल्लेखनीय ढंग से देश में खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है वे निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), जो एटीएम का विशाल नेटवर्क है, ने बिल भुगतान जैसे मूल्य-योजित सेवाएं सुगम बनाने के अलावा ग्राहकों के लिए नकदी आहरण और अन्य बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्धता बढ़ाई है।

- चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) - इसे देशभर में तीन ग्रिड स्थानों में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया है जिससे संसाधित चेक मात्रा का 85 प्रतिशत समाविष्ट है। एनपीसीआई ने अब सीटीएस में संसाधित चेकों की इमेज़ेस की रिपोज़िटरी को सुगम बनाना आरंभ किया है।

- त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) जो पिछले कुछ वर्षों में अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली के रूप में अक्तूबर 2010 में प्रारंभ हुआ था, वह देश में बहु-चैनल 24 x 7 विप्रेषण प्लाटफार्म में परिवर्तित हो गया और यह नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बीसी पाइंट पर, शाखाओं में तथा एटीएम पर उपलब्ध है।

- रुपे एक घरेलू कार्ड प्रणाली जो 2011 में लांच किया गया था, ने धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल की है तथा जन-धन योजना के अंतर्गत उसकी सहलग्नता से यह एक पारिवारिक नाम बन गया है।

- बैंक खातों के साथ बायोमेट्रिक आइडेन्टिफायर की सहलग्नता के माध्यम से आधार आधारित भुगतान लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ भुगतान उपलब्ध करा रहा है और यह देश में वित्तीय समावेशन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

- राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लॉटफार्म (एनयूयूपी) - एक अंतः प्रचालनीय यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लॉटफार्म की स्थापना अपने आप में एक अनूठा कमाल है क्योंकि यह सभी टेलकोस और सभी प्रमुख बैंकों को जोड़ता है तथा लगभग 11 भाषाओं में सेवाएं प्रदान कराता है। इससे काफी उम्मीद है तथा वित्तीय समावेशन सक्षम बनाने में इसकी संभाव्यता बहुत अधिक है।

10. एनपीसीआई की अब तक की यात्रा में उपर्युक्त मदें कतिपय मील का पत्थर हैं। मैं तहेदिल से आशा करता हूं कि एनपीसीआई, भुगतानों की बड़ी मात्रा जो ईलेक्ट्रानिक मोड में नागरिकों को सामाजिक लाभ वितरित करने के लिए सरकार के हाल ही के उपक्रम के कारण उत्पन्न हुई है, उसे संभालने के लिए तैयारी करें।

वैश्विक सफलता की कहानियां दोहराना

11. भुगतान प्रणाली के कार्यक्षेत्र में विश्व भर के विभिन्न भूगोल के भीतर कई सफलता कहानियां हैं। कुछ का उल्लेख किया जा सकता है जैसे - कैनया का एम-पेसा प्रणाली, सिंगापुर में 'टैप एंड गो' कार्ड योजना, चीन का यूनियन पे कार्ड योजना। यदि इन मॉडेलों ने बढ़िया काम किया है और अपने-अपने देशों में सफलता हासिल की है तो क्या हम हमारे अधिकार-क्षेत्र में इन मॉडेल को बस दोहरा नहीं सकते? मुझे डर है कि जवाब नहीं में होगा। मैं भारत का उदाहरण देते हुए बताना चाहुंगा कि ये क्यों नहीं है।

12. भारत में सामाजिक रिवाज, संस्कृति, आस्था के संदर्भ में अनेकता है। जनसंख्या की विविधता और आधिक्य तथा देश का भौगोलिक फैलाव कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे कार्य को अत्यंत जटिल बना देता है। जिस सहजता से लोग प्रौद्योगिकी को संभाल सकते हैं वह भी अलग-अलग आयु-वर्ग के लोग, आय स्तरों, साक्षरता स्तरों आदि के अनुसार भिन्न होता है। अतः ऐसा उत्पाद तैयार करने में मुश्किल होगी जो समाज के सभी वर्गों में अखंड कार्य कर सकें। अतः यह सच है कि कोई भी योजना या मॉडेल अखंड रूप से सभी अर्थव्यवस्थाओं में कार्य नहीं कर सकती तथापि सबसे अच्छी बात यह होगी कि अन्य सफल डेलीवरी मॉडलों से सीख ली जाए और उस उत्पाद तथा सेवा प्रस्तावों को संबंधित अर्थव्यवस्था और समाज के डीएनए के अनुरूप बनाया जाए।

प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणाली

13. मोबाइल और इंटरनेट समझ में वृद्धि ने भुगतान प्रणाली सेवाओं के लिए नए दरवाज़े खोल दिए हैं। जिस तरह से नई पीढ़ी अपना कारोबार करती है उससे यह प्रतिबिंबित होता है । 'बैंक 3.0' के लेखक ब्रेट किंग ने कहा है :

> *''ग्राहक एक दूसरे से दूरी के कारण चैनल या उत्पादों का उपयोग नहीं करते। ग्राहक प्रतिदिन बैंकों के साथ विभिन्न प्रकार से संपर्क करता है। वे किसी तीसरी पार्टी को तार से पैसा भेज सकते हैं, नकदी आहरित करने के लिए एटीएम जा सकते हैं, वेतन जमाशेष देखने के लिए ऑन-लाइन जा सकते हैं, उपयोगिता बिल का भुगतान कर सकते हैं, किसी खुदरा व्यापारी से सामान खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ऑन लाइन व्यैक्तिक ऋण आवेदन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड शेष देखने या खोया हुआ कार्ड की रिपोर्ट करने कॉल सेन्टर से संपर्क कर सकते हैं। अधिक विवेक होने के कारण वे कुछ स्टॉक में व्यापार कर सकते हैं, अपने यूरो खाते में से अमरीकी डॉलर खाते में थोड़ा नकद अंतरित कर सकते हैं , म्युच्युअल फंड में एकमुश्त राशि रख सकते हैं या आवास बीमा नीति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं''।*

14. उक्त कथन बैंकिंग आवेदनों के विविध प्रकार की ओर संकेत करता है जिसे प्रौद्योगिकी समर्थन दे सकता है। वास्तव में, बहुविध उत्पाद प्रस्तावों के लिए एकल चैनल समाधान की जरूरत है। तथापि, यह ज्ञात हो कि प्रौद्योगिकी केवल एक सक्षम योग्य है। लगभग भारत में सभी बैंकों ने वेब-आधारित और मोबाइल-आधारित डेलीवेरी बैंकिंग और भुगतान सोल्यूशन में बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया हुआ है। प्रायः इन चैनलों को अलग-अलग विक्रेताओं से समर्थन प्राप्त होता है और प्रत्येक भिन्न-भिन्न तकनीकी का उपयोग करते हैं जो जटिलता बढ़ाता है और

अधिक लागत लगती है। प्रौद्योगिकी हमेशा विकसित होती रहती है और समसामायिक रहने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाना महंगा प्रस्ताव है। अतः यह प्रासंगिक है कि प्रौद्योगिकी समर्थित डेलीवेरी सोल्यूशन की सभी क्षमताओं का किफायती रूप से लाभ उठाया जाए ताकि हम अनुत्पादक निवेशों से न लद जाए।

15. जबकि चारों ओर मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल भुगतानों को अपनाने का उत्साह है, कुछ देशों जहां सही वातावरण कारक मौजूद हैं , को छोड़कर, यह मॉडेल अपेक्षाकृत कम सफल रहा है। मैं यहां वित्तीय और भुगतान सेवाओं को इंटरनेट बैंकिंग आदि हेतु एक्सेस चैनल के रूप में प्रयोग करने के बजाय उसे मोबाइल डीवाइस के माध्यम से प्रदान करने की बात कर रहा हूँ। भारतीय संदर्भ में, एक उद्देश्यपरक विश्लेषण से धीमी गति के अभिग्रहण के कई कारण उजागर हो सकते हैं। ऐसे कई तकनीकी मामले हैं जैसे हैंडसेट के प्रकार, परिचालन प्रणाली में विविधता, कुटलेखन की अपेक्षाएं, अंतः प्रचालनीय प्लाटफॉर्म या उसका अभाव, मानक संप्रेषण संरचना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में परेशानियां,एक्टिवेशन में समय-अंतराल आदि। ये ऑन-बोर्डिंग व्यापारियों और ग्राहकों तथा ग्राहक स्वामित्व मामलों में परिचालन-संबंधी परेशानियों द्वारा अधिक सुस्पष्ट हो जाते हैं। इन कारकों के पारस्परिक प्रभाव ने मोबाइल बैंकिंग को प्रभावी और व्यापक रूप से अपनाई गई डिलेवरी चैनल के रूप में स्वीकार करने और उसके प्रसार को बाधित किया है। बैंकों और टेलकोस के बीच समन्वय और सहयोग के मामले एक दूसरा पहलू है जो मोबाइल बैंकिंग के स्वीकरण में या तो चालक या बाधक की भूमिका निभाता है। यदि हमारे देश में, मोबाइल भुगतानों को सफल बनाना है तो इन मामलों का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है।

उभरता परिदृश्य

16. यहां यह दिलचस्प होगा यदि भविष्य में उभरने वाले कतिपय परिदृश्यों की कल्पना की जाए :

- रीड्स कानून और मूरस् कानून प्रभाव को साथ-साथ लेने से अंतराल के भीतर 'भुगतान अंतराल' और निर्दिष्ट दोनों घातांक रूप से बढ़ेंगे।
- क्या कतिपय तकनीकी कंपनियां और खुदरा बैंक इस हद तक बदलाव कर सकते हैं कि तकनीकी फर्म खुदरा बैंक लगे और खुदरा बैंक तकनीकी फर्म लगे।
- एक बैंक और एक गैर-बैंक के बीच अधिकाधिक सहकार्य हो।
- माइक्रो भुगतानों से मोबाइल की ओर क्रमिक स्थानांतरण जिससे भौतिक मुद्रा नोटों और सिक्कों की आवश्यकताओं में कमी आए।
- मुद्रा वितरण के समान मोबाइल वॉलेट पर सीधे वेतन और भुगतान का वितरण।
- नकदी लेन-देनों में कमी के कारण एटीएम को योग्य रहने के लिए केवल नकद बांटने के बजाय अन्य सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- बटन क्लिक करते ही केवाईसी, व्यापक बाजार क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से ऋण की सहुलियत।
- क्या भविष्य में मोबाइल पर सीमा-पार लेन-देन हो सकते हैं?

भुगतान प्रणाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ते हुए ऐसी संभावनाओं को समायोजित करने और उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

विनियामक चुनौतियां

17. भुगतान प्रणाली अंतराल में नवीन प्रक्रिया तथा नए उत्पादों का आगमन रेगुलेटरों को चुनौतियां दे रहा है और आगे चलकर ये चुनौतियां तीव्र होने की संभावना है। कतिपय संभाव्य दुविधाएं/चुनौतियां जिसका सामना रेगुलेटरों को भविष्य में करना पड़ेगा वे हैं :

- क्या भुगतान और निपटान बैंक के पास सुरक्षित रहेगा? यदि नहीं, तो नियंत्रक अवस्थिति क्या होगी?

- वास्तविक मुद्राओं को विनियमित करने में आगे के क्या उपाय होंगे?
- क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा।
- कारोबार करने में सहुलियत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन बनाए रखना।
- मोबाइल लेन-देनों से चुनौतियां लेन-देन केन्द्रित के बजाय अधिक यूज़र केन्द्रित बनाना।
- क्रॉस करेंसी / क्रॉस-बार्डर मोबाइल लेन-देनों की निगरानी अभी नहीं लेकिन जब ऐसे लेन-देन होते हैं।

नियामक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी ''उमसदार नवोन्मेष की कीमत पर नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन'' प्रदान करने हेतु तंग रस्सी पर चलना जैसे होगा।

निष्कर्ष

18. मैं एनपीसीआई को इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए दुबारा बधाई देते हुए भाषण समाप्त करना चाहुँगा। इस संस्थान ने अब तक मुश्किल चुनौतियों को पराजित किया है तथा खुदरा भुगतान कार्यक्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। तथापि, यह केवल एक शुरुआत है। इसे दक्ष रहने की आवश्यकता है तथा एक गतिशील विश्व से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए लागातार नई खोज करते रहना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले भी कहा था ऐसे सम्मेलन विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होता है। मैं आशा करता हूँ सहभागियों को यहां से कुछ लेकर जाने के लिए सार्थक सामग्री प्राप्त हुई होगी जो मजबूत और सफल भुगतान प्रणालियों के ढांचे को आकार देने में मदद करेगा जो लेन-देनों के आधिक्य को संभाल सके और संबंधित कार्यक्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि में सहायक बन सके।

धन्यवाद!